The Research Dialogue

An Online Quarterly Multi-Disciplinary
Peer-Reviewed / Refereed Research Journal
ISSN: 2583-438X
Volume-1, Issue-3, October 2022
www.theresearchdialogue.com

"आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास: राजर्षि छत्रपति शाहूजी महाराज का योगदान"

नीरज वर्मा
शोध अध्येता, डॉ० राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)

डॉ अखिलेश
असिस्टेंट प्रोफेसर, शिक्षक शिक्षा विभाग,रामनगर पी० जी० कालेज रामनगर, बाराबंकी (उ०प्र०)

सारांश :

शिक्षा एक ऐसी सतत प्रक्रिया है जो मानवीय जीवन को बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न बनाती है। शिक्षा विहीन मनुष्य का जीवन एकांगी व नीरस होता है। बिना शिक्षा के न तो नैतिकता का बोध होता है और न ही भौतिक जगत का। शिक्षा ही शक्ति और समृधि का मूलाधार है। सुदृढ़ शासन और प्रगति का मुख्य आधार ही शिक्षा है। इन्ही विचारों से प्रेरित होकर छत्रपति शाहूजी महाराज ने अपना ध्यान समाज की शिक्षा पर केन्द्रित किया।

प्रस्तुत शोध पत्र में छत्रपति शाहूजी महाराज द्वारा शिक्षा में किये गए योगदान का विश्लेषण किया गया है। इसमें उनके द्वारा सभी के लिए शिक्षा का विचार, निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, महिला शिक्षा, कृषि शिक्षा, शिक्षा प्रदान करने के लिए अपनाई गई रणनीति, जन शिक्षा के लिए किए गए उनके प्रयास सम्मिलित हैं।

शब्द कुंजी: *प्राथमिक शिक्षा, सामाजिक समता व न्याय, आरक्षण ।*

प्रस्तावना :

प्लेटो ने अपनी चर्चित पुस्तक 'रिपब्लिक' में एक ऐसे राजा की कल्पना की है जिसमें दार्शनिक जैसी मानवीय गरिमा, साहस और राजनीतिक श्रेष्ठता एवं बौद्धिकता का मेल हो। उसका कहना था कि ऐसा राजा मानव जाति को तमाम अभिशाप से मुक्त कर सकता है और अंधेरे से निकाल कर रोशनी की ओर ले जा सकता है। भारत में ऐसे राजाओं की गिनी-चुनी मिसालें ही हैं। उनमें से एक हैं - छत्रपति शाहूजी महाराज (26 जून, 1874- 6 मई, 1922), जिन्होंने अपने राज्य कोल्हापुर की करीब 90 प्रतिशत आबादी को उन सभी अभिशापों से मुक्त करने के लिए ऐसे ठोस एवं निर्णायक उपाय किए, जो अभिशाप उनके ऊपर जाति व्यवस्था ने लाद रखे थे। उन्नीसवीं सदी में सामाजिक- धार्मिक सुधारों को करने की प्रक्रिया इतनी आसान नही थी।

हर काल में क्रांति चाहे सामाजिक रही हो या आर्थिक अथवा राजनीतिक, क्रांति के हर सूत्रधार को परंपरा जीवित जड़ता में ग्रस्त प्रतिद्वंदियों का कठोर विरोध भी झेलना पड़ता है इसके साथ सामान्य लोक भावना भी क्रांतिकारी पुरुषों का साथ देने में हिचकिचाती हैं। संसार के विभिन्न देशों के क्रांतिकारियों को विरोध का अभिशाप निरंतर सहना पड़ा किंतु इसी के साथ हमें यह भी याद रखना होगा कि क्रांति के छोटे-छोटे स्फुलिंग अंततोगत्वा भीषण ज्वाला का रूप धारण करते हैं तथा प्रतिक्रियावादी शक्तियों को भस्म कर एक नए समाज की रचना करते हैं। छत्रपति शाहूजी महाराज ने जब तत्कालीन धर्म के ठेकेदारों से सामाजिक समानता की बात कही तो वे उनका विरोध करने पर उतर आए। छत्रपति शाहूजी जातियों और वर्णों में खंडित भारत को सामाजिक समानता तथा भेदभाव रहित अखंड राष्ट्रीयता के सूत्र में बांधना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन के अस्त्र के रूप में चुना। उनका मानना था कि शिक्षा ही शक्ति और समृधि का मूलाधार है। सुदृढ़ शासन और प्रगति का मुख्य आधार ही शिक्षा है। इन्ही विचारों से प्रेरित होकर छत्रपति शाहूजी महाराज ने अपना ध्यान समाज की शिक्षा पर केन्द्रित किया। छत्रपति शाहूजी महाराज ने अपनी राजगद्दी के लोभ का सर्वथा त्याग किया और अपने राज्य में दलितों, पिछड़ों, निर्बल और अछूतों की शिक्षा व सामाजिक समानता के लिए आजीवन संघर्षरत रहे।

जीवन परिचय

छत्रपति शाहूजी का जन्म 26 जून 1874 को कोल्हापुर रियासत के रीजेंट जयसिंहराव अप्पा घाटगे के घर माता राधाबाई की कोख से कुर्मी (कुन्वी) जाति में हुआ था। शाहूजी के बचपन का नाम यशवंत राव था। जब ये केवल तीन वर्ष थे तभी उनकी माता का देहांत हो गया था। पिता जयसिंहराव अप्पा घाटगे ने उनकी प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था कोल्हापुर में ही की थी। यशवंत राव को कोल्हापुर रियासत के राजा शिवाजी चतुर्थ की विधवा रानी आनंदीबाई ने 17 मार्च सन 1884 को गोद लिया था। शाहूजी ने अपनी उच्च शिक्षा राजकुमार कॉलेज, राजकोट में पूरी की और भारतीय सिविल सेवा के प्रतिनिधि सर स्टुअर्ट फ्रेजर से प्रशासनिक मामलों की शिक्षा ली। 20 मार्च 1886 को इनके पिता अप्पा घाटगे की मृत्यु हो गयी। 2 अप्रैल 1894 को शाहूजी सिंहासन पर आरूढ़ हुए और राज्यसत्ता संचालन के सभी अधिकार अपने हाथों में लिए, इससे पूर्व ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त एक रीजेंसी काउंसिल राज्य के मामलों का ध्यान रखती थी। उनके राज्यारोहण के दौरान यशवंतराव का नाम बदलकर शाहूजी महाराज कर दिया गया। उनका विवाह 1891 में बड़ौदा के मराठा सरदार गुंजीराव खानविलकर की पुत्री लक्ष्मीबाई खानविलकर से हुआ

था। शाहूजी दंपति के चार संतानें थी। शाहूजी आजीवन बहुजनों को सामाजिक समानता और न्याय दिलाने के लिए प्रयासरत रहे। इस महामानव का निधन 06 मई 1922 को हुआ।

शैक्षिक कार्य

छत्रपति शाहूजी का मानना था कि समाज की प्रगति में कई बाधक तत्व हैं उनमें से एक है जाति-व्यवस्था। उनका कहना था कि जब तक इस जाति का विनाश नही होगा तब तक सामाजिक समता व सामाजिक न्याय स्थापित नही हो सकता और मनुष्यता की दुनिया नही बन सकती। छत्रपति शाहू महाराज जानते थे कि समाज में सभी को समानता बिना शिक्षा दिए संभव नहीं है। पारंपरिक समाज में कई अंधविश्वास, विचार और विश्वास थे जिन्होंने समाज में समानता के सिद्धांत पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रखा था। शाहूजी के अनुसार शिक्षा एक ऐसा हथियार है जो जीवन के युद्ध में बहुत उपयोगी है, इस युग में जीवित रहने के लिए संघर्ष बढ़ रहा है और केवल शिक्षित ही जीवित रहेगा। उनका विचार था कि उचित पोषण के बिना मनुष्य कमजोर हो जाता है और ज्ञान के बिना मनुष्य पिछड़ा हो जाता है। इसलिए शिक्षा कई समस्याओं को हल करने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। वे जानते थे कि जनता का सर्वांगीण विकास शिक्षा के द्वारा ही संभव हो सकता है। इसलिए उन्होंने सत्ता संभालते ही तत्कालीन शिक्षा प्रणाली के अध्ययन एवं सुधार हेतु 'शिक्षा सुधार समिति' गठित की। शाहूजी की शैक्षिक नीति अत्यंत स्पष्ट एवं सरल थी जिसका उद्देश्य था कि समाज के सभी वर्गों को शिक्षा के समान अवसर प्राप्त हों व शिक्षा से वंचित वर्गों में अधिकाधिक शिक्षा का संचार हो जिससे सामाजिक परिवर्तन हो सके। शाहूजी के समय में शिक्षा पर उच्च वर्ग का आधिपत्य था। शिक्षा के अभाव में समाज के बहुसंख्यक वर्ग की स्थिति अत्यंत दयनीय थी, यह स्थिति शाहूजी महाराज के लिए चुनौती थी। इसके निराकरण के लिए उन्होंने सार्वजनिक शिक्षा की व्यवस्था पर बल दिया। उन्होंने विभिन्न पिछड़ी जातियों के लिए विद्यालयों एवं छात्रावासों का निर्माण कराया। शिक्षा सर्वसुलभ हो सके इसलिए प्रत्येक गाँव में प्राथमिक विद्यालय की स्थापना करवाई व उनमें पढने वाले अधिसंख्यक विद्यार्थियों की जाति से सम्बंधित शिक्षक की नियुक्ति की। राज्य में संचालित निजी विद्यालयों को वित्तीय सहायता का प्रबंध किया जिससे शिक्षा के प्रसार को गति मिल सके। शाहूजी ने प्रशिक्षित शिक्षकों के महत्त्व को ध्यान में रखते हुए कई ट्रेनिंग स्कूल खोले। छत्रपति शाहूजी स्त्रियों की सामाजिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए भी चिंतित थे। इसलिए उन्होंने अपने शासनकाल में अनेको बालिका विद्यालयों की स्थापना की शाहूजी ने जीवन पर्यंत संघर्ष करते हुए अपने राज्य के लोगों के लिए ऐसी शिक्षा की व्यवस्था की जो उनके सामाजिक और आर्थिक उन्नति का सहारा बने। उनके द्वारा किये गए शैक्षिक सुधारों ने समाज को एक नयी दिशा देने का कार्य किया। अस्पृश्य / बहुजनों की शिक्षा व्यवस्था

छत्रपति शाहूजी महाराज ने अस्पृश्यों के लिए स्कूल और छात्रावास खोलकर उनके विकास का मार्ग प्रशस्त किया। ऐसा करते हुए, उन्होंने अस्पृश्य समुदाय से पूर्वाग्रहों को मिटाने के लिए कड़ी मेहनत की और शिक्षा में समान अवसर प्रदान करने पर जोर दिया। उन्होंने अपने प्रांत में शिक्षा के माध्यम से पिछड़े समुदायों के उत्थान की नीति अपनाई। कोल्हापुर में विभिन्न समुदायों के छात्रों के लिए कई छात्रावास स्थापित किए गए थे। उन्होंने इस काम के लिए 'शिक्षा प्रसार बोर्ड' (विद्या प्रसार मंडल) नामक एक संगठन की स्थापना की, लेकिन अस्पृश्यों को शिक्षा के लिए राजी करना कठिन काम था क्योंकि वे शिक्षा के प्रति उदासीन थे। इसलिए इन मुद्दों को दूर करने के लिए शाहूजी महाराज ने कड़ी मेहनत की। उनके राज्याभिषेक के समय उनके प्रांत में केवल 05 स्कूल अस्पृश्यों के लिए मौजूद थे और छात्रों की संख्या 168 थी। 1907-1908 के दौरान

अस्पृश्यों के लिए स्कूलों की संख्या 16 हो गई और छात्रों की संख्या 416 हो गई। महाराज के अथक प्रयासों से अस्पृश्यों के लिए स्कूलों की संख्या धीरे-धीरे बढ़ती गई। 1912 में, अस्पृश्यों के लिए स्कूलों की संख्या 27 हो गई और इन चार वर्षों के दौरान छात्रों की संख्या 636 हो गई। वह व्यक्तिगत रूप से इन योजनाओं के वित्तीय प्रावधानों का अवलोकन करते थे। छत्रपति शाहूजी महाराज और भाऊराव पाटिल ने सतारा जिले में शैक्षिक रूप से पिछड़े समुदायों के बीच शिक्षा के प्रसार के लिए धन संग्रह की एक अनूठी योजना तैयार की। उन्हें कुश्ती में बहुत दिलचस्पी थी और उनके संरक्षण में कई पहलवान थे। उस समय कोल्हापुर प्रांत में लोग कुश्ती में बहुत रुचि रखते थे। उन्होंने विभिन्न गांवों में कुश्ती मैचों के टिकट बेचने की योजना को अंजाम दिया और उससे प्राप्त धन को शिक्षा के प्रसार पर खर्च किया। छत्रपति शाहूजी महाराज ने अपने प्रांत में अस्पृश्यों के लिए छात्रावासों का निर्माण शुरू किया और अस्पृश्यों के बीच शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नए शिक्षकों की नियुक्ति की। 1907 में उन्होंने कोल्हापुर में डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन की एक शाखा की स्थापना की। इसी मिशन के तहत 'मिस क्लार्क स्टूडेंट हॉस्टल' की स्थापना की गई। इसके अलावा, उन्होंने अपने महल में 50 अस्पृश्य छात्रों के लिए एक मुफ्त छात्रावास और मेस खोला। उन्होंने अपने प्रांत में इस काम को अंतहीन रूप से जारी रखा। उन्होंने उन संगठनों के लिए भी उदारता से दान दिया जो अस्पृश्यों के उत्थान के लिए समर्पित थे। अस्पृश्यों में शिक्षा के प्रसार के लिए उन्होंने 24 नवंबर 1911 को सबसे महत्वपूर्ण आदेश जारी किया। इस आदेश के अनुसार उनके प्रांत में अस्पृश्यों के लिए सभी प्रकार की शिक्षा निशुल्क कर दी गई थी। अस्पृश्यों के मेधावी विद्यार्थियों को सरकार की ओर से विशेष छात्रवृत्ति दी जाती थी। उन्होंने अस्पृश्यों के बीच शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 7 अप्रैल 1919 को एक आदेश जारी कर दो हजार पांच सौ रुपये की मंजूरी दी और उन्हें किताबें, स्लेट और पेंसिल की पेशकश की। उनके एक आदेश में कहा गया है कि, 'प्रांत के शिक्षा विभाग को अस्पृश्यों और मुख्यधारा के लोगों जैसे अमेरिकी मिशन, सेंट जेवियर, विल्सन कॉलेज और आर्य सोसाइटी के स्कूलों, कॉलेजों और आवासीय स्कूलों में बिना किसी भेदभाव के सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों को अस्पृश्य छात्रों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करना चाहिए और उन्हें स्कूलों में नामांकित करना चाहिए' (कीर, 1976)। उन्होंने आशा व्यक्त की कि जो निजी और सरकारी संगठन शिक्षा विभाग के तहत भवन और मुफ्त जमीन के रूप में अनुदान प्राप्त करते हैं, वे अछूतों के साथ उच्च जाति के लोगों की तुलना में अधिक स्नेह और सम्मान के साथ व्यवहार करें। मुख्यधारा के लोगों के पास खुद को शिक्षित करने के कई तरीके हैं लेकिन, अस्पृश्यों के पास इसे हासिल करने के लिए ऐसे माध्यम नहीं हैं। यदि प्रधानाचार्य या शिक्षक अस्पृश्यों के साथ समान व्यवहार करने में विफल रहते हैं, तो उन्हें दंडित करने का प्रावधान किया साथ ही, ऐसे मामलों में निजी संस्थान का अनुदान रद्द करने के आदेश दिए। शाहू महाराज द्वारा जारी एक अन्य आदेश के अनुसार, यदि स्कूल विभाग का कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता है, तो उन्हें छह सप्ताह के भीतर अपना त्याग पत्र भेजना चाहिए। उसे पेंशन नहीं मिलेगी। अनुदानित और अन्य सहायता प्राप्त संगठन इसका उल्लंघन करता है तो उसकी मान्यता रद्द कर दी जायेगी। इस प्रकार शाहू महाराज के आंदोलन ने पिछड़े वर्गों के बीच शिक्षा के प्रति रुचि विकसित की और उन्हें उनके मानवाधिकारों के बारे में जागरूक किया। शाहूजी महाराज के शैक्षिक कार्यों ने अस्पृश्यों को उनकी स्थिति के बारे में जागरूक किया और उनके प्रांत में अस्पृश्यों की शिक्षा के अनुपात में वृद्धि की।

निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का विचार

सामान्य तौर पर यह पाया गया है कि नौकरशाही और प्रशासनिक शक्ति हमेशा शिक्षित और आर्थिक रूप से सशक्त लोगों के हाथ में होती है लेकिन शिक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण के बीच घनिष्ठ संबंध है इससे वे भलीभांति परिचित थे। शिक्षा और अधिकारिता के बीच इस संबंध का प्रयोग छत्रपति शाहूजी द्वारा अपने राज्य में निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अपने विचार के माध्यम से किया गया। शाहूजी महाराज दलित वर्गों को शिक्षा के क्षेत्र में और अपने राज्य की प्रशासनिक प्रक्रिया को बढ़ावा देना चाहते थे। इसलिए उन्होंने **निशुल्क** शिक्षा का विचार शुरू किया। शिक्षा के माध्यम से वे निचली जाति के समुदाय को प्रशासन में शामिल करना चाहते थे। उनके काल में अस्पृश्यों को शिक्षा के दीर्घकालीन लाभों की जानकारी नहीं थी। अत: छत्रपति शाहूजी ने उन सभी को अनिवार्य रूप में शिक्षा प्रदान करने का निर्णय लिया। वह प्रशासन और नौकरशाही में सवर्ण समुदायों की केंद्रित शक्ति से परिचित थे। इसलिए उन्होंने महसूस किया कि निचली जातियों को सत्ता हस्तांतरित करने से पहले पूरे समाज में ज्ञान का प्रसार करना आवश्यक है। इसलिए उन्होंने सभी के लिए शिक्षा अनिवार्य कर दी। उनका विचार था कि निशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा ही एकमात्र स्फूर्तिदायक टॉनिक है जो निम्न वर्गों को अतीत के बोझ को उतारने में सक्षम बनाएगी (कुंभर, 1992)। छत्रपति शाहूजी महाराज का मानना था कि शिक्षा के बिना कोई भी देश प्रगति नहीं कर सकता है। सर्वश्रेष्ठ राजनेता, महान योद्धा एक अनपढ़ देश में पैदा नहीं होते (कीर, 1976)। इसलिए लोगों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना जरूरी है। उन्होंने जनता के लिए शिक्षा के महत्व और इसे निशुल्क और अनिवार्य बनाने की आवश्यकता की पहचान की। उत्तरजीविता और राष्ट्रीय प्रगति के लिए शिक्षा आवश्यक है, इसलिए माता-पिता को अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए मजबूर करने के लिए छत्रपति शाहूजी महाराज ने एक घोषणा जारी की कि सभी माता-पिता की यह जिम्मेदारी है कि वे अपने बच्चों को स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्कूल भेजें। यदि वे इसमें देरी करते हैं, तो ममलेदार प्रत्येक माता-पिता पर 1 रुपये प्रति माह का जुर्माना लगायेंगे। शाहूजी महाराज ने 1911 से समाज के पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति कार्यक्रम की स्थापना की। शैक्षिक व्यय को वहन करने के लिए, उन्होंने अधिकारियों, डॉक्टरों और व्यापारियों पर कर लगाया जिनकी आय 100 रुपये से अधिक थी वे शैक्षिक उपकर के लिए अपनी आय का 2% भुगतान करते थे।

उच्च शिक्षा

छत्रपति शाहूजी महाराज ने न केवल प्राथमिक शिक्षा बल्कि उच्च शिक्षा के महत्व को भी पहचाना है। 1910-11 के दौरान उन्होंने 1911-12 में 15 छात्रों और 10 छात्रों को बॉम्बे (मुंबई), पुणे, मद्रास (चेन्नई) और अन्य स्थानों में उच्च शिक्षा लेने के लिए भेजा। उच्च शिक्षा के संबंध में शाहू महाराज ने इन छात्रों को न केवल पारंपरिक शिक्षा लेने के लिए बल्कि चिकित्सा विज्ञान में व्यावसायिक शिक्षा के लिए भी भेजा। 1913-14 के दौरान उन्होंने 6 छात्रों को मेडिकल कॉलेज, बॉम्बे, मेडिकल स्कूल पोन्ना, पूना ट्रेनिंग कॉलेज और डेक्कन कॉलेज, पुणे में भेजा।

कृषि शिक्षा

राज्य में कृषि शिक्षा के महत्व को देखते हुए छत्रपति शाहूजी महाराज ने किंग एडवर्ड कृषि संस्थान,कोल्हापुर(1912) की शुरुआत की थी।यह संस्थान आधुनिक कृषि में शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए विशेष था। इस उद्देश्य के लिए उन्होंने 30 हजार रुपये का दान एकत्र किया और इसे राज्य के खजाने में 6 प्रतिशत ब्याज दर पर जमा किया, उन्होंने इसमें स्वयं प्रति वर्ष 1200 रुपये अपनी तरफ से दिए जिससे कृषि शिक्षा देने हेतु बेहतर शिक्षकों की नियुक्ति व उन्हें बेहतर सुविधाएँ दी जा सकें। उनका मानना था कि दिन-प्रतिदिन कृषि व्यवस्थित होती जा रही है और कृषि में सफलता पाने के लिए हमें उस विषय पर किताबें पढ़नी चाहिए। यह दर्शाता है कि भारत में कृषि शिक्षा के संबंध में महाराज के कितने अच्छे विचार थे और

वे कितने दूरदर्शी थे।

महिलाओं के लिए शिक्षा

शाहूजी महाराज के समय में धार्मिक और रुढ़िवादी परम्पराओं की मान्यताओं के कारण महिलाओं की स्थिति अमानवीय थी। समकालीन समाज में बाल विवाह, देवदासी प्रथा, विधवा महिलाओं का शारीरिक और मानसिक शोषण अस्तित्व में थी। शाहूजी महाराज का मानना था कि महिलाओं को शोषण से मुक्ति और विकास के लिए आत्मनिर्भर होने की जरुरत है, जिसमें शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। महिलाओं की शिक्षा के लिए शाहूजी महाराज ने महत्वपूर्ण प्रयास किए, खासकर पिछड़े समुदायों की महिलाओं के लिए 3 मार्च 1913 को उन्होंने राधाबाई अक्कासाहेब महाराज छात्रवृत्ति और श्री नंदकुवर महारानी, भावनगर, कोल्हापुर राज्य में महिला छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की घोषणा की। जैसा कि नटराजन, 1966 ने अपने लेखन में दर्ज किया है कि उस समय की पिछड़ी जाति की लड़कियां स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षा लेने में झिझकती थीं, इसलिए इस समस्या को हल करने के लिए महाराज ने छात्राओं को आश्वस्त करने के लिए पिछड़े समुदायों की महिला सेवकों को नियुक्त किया था। छत्रपति शाहू महाराज ने छात्राओं को अंग्रेजी भाषा की शिक्षा प्रदान करने का भी प्रयास किया। 1911 से 1914 तक कुल 8369 लड़कियों ने इस प्रणाली के माध्यम से शिक्षा प्राप्त की थी।

निष्कर्ष

छत्रपति शाहूजी महाराज स्वभाव से दूरदर्शी और वास्तव में लोकतांत्रिक थे और शिक्षा के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन लाने की उनकी महत्वाकांक्षा थी। उन्होंने सामाजिक परिवर्तन, पिछड़ों के सशक्तिकरण, महिलाओं और सामाजिक रूप से वंचित लोगों के सशक्तिकरण में शिक्षा के महत्व को महसूस किया। छत्रपति शाहूजी महाराज विभिन्न प्रकार की शिक्षा और प्रशिक्षण से भी अवगत थे, उन्होंने न केवल पारंपरिक शिक्षा पर अपना ध्यान केंद्रित किया, बल्कि औद्योगिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, कृषि शिक्षा के लिए भी प्रयास किए। सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने उस युग में सभी के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की अवधारणा को महसूस किया। उन्होंने न केवल इसे महसूस किया, बल्कि सामाजिक परिवर्तन के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को बढ़ावा देने के व्यापक कार्यक्रम पर भी काम किया।

मेरा मानना है कि इन रणनीतियों का महत्व खत्म नहीं हुआ है, वर्तमान परिदृश्य में उनकी प्रासंगिकता और आवश्यकता अभी भी है। छत्रपति शाहूजी महाराज ने सभी के लिए निशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा पर काम किया था, अब सभी के लिए निशुल्क और अनिवार्य कौशल शिक्षा की आवश्यकता है। कौशल शिक्षा या तो कृषि, तकनीकी शिक्षा, व्यापार शिक्षा, सेवा क्षेत्र में कौशल-उन्मुख शिक्षा, औद्योगिक शिक्षा में हो सकती है। यदि हम छत्रपति शाहूजी महाराज की दृष्टि की भावना को अपनाते हैं तो यह निश्चित रूप से समावेशी शिक्षा के माध्यम से भारतीय समाज में बदलाव लाएगी।

संदर्भ

1. भगत, आर० टी, (1999) ; शिक्षामहर्षि राजर्षि शाहू महाराज, सिद्धराज प्रकाशन, पुणे।

2. कवलेकर, के०के (1979) ; गैर-ब्राह्मण आंदोलन दक्षिणी भारत, शिवाजी विश्वविद्यालय,कोल्हापुर ।

3. कीर, धनंजय (1976) ; 'शाहू छत्रपति: एक शाही क्रांतिकारी', लोकप्रिय प्रकाशन, बॉम्बे।

4. कुंभर, नागोजीराव (1992) ; 'राजर्षि शाहू महाराज', प्रबोधन प्रकाशन, लातूर।

5. सिंह, श्याम सुन्दर (2016) ; 'छत्रपति शाहूजी महाराज संघर्ष और इतिहास', सम्यक प्रकाशन, दिल्ली।

6. महोपारे, राहुल (2006) ; 'आर्थिक नीतियां और राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज के कार्यक्रम' पी-एच०डी० थीसिस, शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापकोल्हापुर। http://hdl.handle.net/10603/135782 Retrived on 02/09/2022

THE RESEARCH DIALOGUE

An Online Quarterly Multi-Disciplinary
Peer-Reviewed / Refereed Research Journal
ISSN: 2583-438X
Volume-1, Issue-3, *October* 2022
www.theresearchdialogue.com
Certificate Number-Oct-2022/10

Certificate Of Publication

This Certificate is proudly presented to

नीरज वर्मा एवं डॉ अखिलेश

For publication of research paper title

"आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास: राजर्षि छत्रपति शाहूजी महाराज का योगदान"

Published in 'The Research Dialogue' Peer-Reviewed / Refereed Research Journal and E-ISSN: 2583-438X, Volume-01, Issue-03, Month October, Year- 2022.

Dr.Neeraj Yadav
Executive Chief Editor

Dr.Lohans Kumar Kalyani
Editor-in-chief

Note: This E-Certificate is valid with published paper and the paper must be available online at www.theresearchdialogue.com